

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 22/ 20

वर्ष 2020

जीसीएम संख्या :-2020/00175

बउनवानी:- 1. महावीर प्रसाद पुत्र माधोलाल माली निवासी, चौथ का बरवाडा

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र भवंर लाल माली निवासी चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ,ग्रा.प.चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

(निगरानी विरुद्ध पट्टा/पत्रावली संख्या 1532 दिनांक 20.9.2017 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थित:-1. श्री अजय शेखर दवे
2. श्री सुधीर कुमार जैन

वकील प्रार्थीगण

वकील अप्रार्थी-1

:- निर्णय :-

दिनांक 07.12.2021

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के द्वारा जारी पट्टा संख्या 22 पत्रावली संख्या 1532 दिनांक 20.9.2017 के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पट्टा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि कस्बा चौथ का बरवाडा में उभयपक्षों का एक पैतृक मकान है जिसमे दोनो पक्ष का आधा-आधा हिस्सा है विपक्षी ने उक्त साझे के मकान को अपना बताते हुए ग्राम पंचायत से पत्रावली संख्या 458 दिनांक 20.2.2004 द्वारा पट्टा बनाया जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 25.11.2005 को निरस्त करते हुए प्रकरण को तीन बिन्दुओं (मौका रिपोर्ट, सम्पत्ति का मालिकाना हक के सबूत तथा भाईयों की सहमति)की पालना करने के निर्देश के साथ ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को रिमाण्ड किया जिस पर ग्राम पंचायत ने उक्त निर्णय को नजर अंदाज कर दुबारा 20.9.2017 को विपक्षी के पक्ष में पट्टा बनाने का निर्णय किया जिसे पुनः न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 15.9.2015 पत्रावली संख्या 7/12 द्वारा ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया। इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दो बार दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर पुनः 20.9.2017 को विपक्षी के पक्ष मे पत्रावली संख्या 1532 द्वारा पुराने पट्टे का नवीनीकरण करने का आलौच्य निर्णय पारित कर दिया जिसके विरुद्ध यह निगरानी पेश की गयी है। यह तर्क भी दिया कि जिस आबादी भूमि का पट्टा विपक्षी के पक्ष में बनाया है वह उपभयपक्षों का पैतृक मकान है ग्राम पंचायत ने भूमि बैचाने के नियमों की अवहेलना करते हुए विपक्षी के पक्ष मे गलत फैसल किया है क्योकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा जिन बिन्दुओं पर पत्रावली को रिमाण्ड किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य निर्णय मे उन बिन्दुओं के बारे मे एक भी शब्द नही लिखा है एवं आपसी मिलीभगत के चलते ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय मे न्यायालय से रिमाण्ड होने के तथ्य भी अंकित नही किये है। यह भी तर्क दिया कि आलौच्य निर्णय में ग्राम पंचायत ने भूमि विक्रय के किसी भी प्रावधान की पालना नही की एवं विपक्षी से मिलीभगत के चलते 7.7.2017 को दिये गये आवेदन के तमाम बिन्दुओं को आपत्ति नोटिस जारी किया जाना ग्राम पंचायत का विपक्षी के साथ मिलीभगत का प्रतीक है। उक्त प्रकरण मे मौका रिपोर्ट व साक्ष्य में भी औपचारिकता निभाई है यही वजह है कि दो बार

.....(1).....

6/12
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर


स्पष्ट मौका रिपोर्ट देने के निर्देशों के बावजूद ग्राम पंचायत के 18.9.2017 को नो लाईन की मौका रिपोर्ट लगा कर निर्णय पारित कर दिया जो सही नहीं था। इसलिए निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

: विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से के पुस्तैनी मकान का पट्टा बनवाया गया है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा कौनसी भूल की है अंकित नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा पट्टा बनवाने बाबत ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 21.8.2017 को पत्रावली पेश हुई जिसपर मौका हेतु रिपोर्ट वार्ड पंच श्री अजीम कुरेशी, श्री मुकेश वर्मा एवं विकास तिलोट को नियुक्त किये जाने पर पत्रावली पट्टा संख्या 458 दिनांक 20.5.2004 से संबंधित पुस्तैनी मकान मौका देखा गया। प्रार्थी शंकर लाल द्वारा पट्टा नवीनीकरण बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त पट्टे से संबंधित भूखण्ड का वार्ड पंचों की टीम द्वारा देखा जाने पर नक्शा अनुसार सही पाये जाने की रिपोर्ट दिनांक 18.9.2017 को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की गयी इसके उपरान्त दिनांक 2100/-रु विकास शुल्क एवं 200/-रु पट्टा शुल्क जमा करते हुए दिनांक 20.9.2017 को नियमानुसार मुझ अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया है जिसके किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी के पक्ष में पत्रावली संख्या 1532 पर पट्टा संख्या 22 दिनांक 20.9.2017 जारी करते समय अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 25.11.2005 एवं 15.9.2015 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए कार्यवाही की गयी हो मूल मिसल की आदेशिका से साबित नहीं होता है। उक्त पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा केवल मौका रिपोर्ट ही तलब की गयी है शेष उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज तथा प्रभावित पक्षकारान की ओर से सहमति पत्र इत्यादि पेश नहीं किया है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा जारी करते समय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित पूर्व निर्णयों की पालना नहीं की जाने के कारण उक्त पट्टा विधिसम्मत होना प्रतीत नहीं होता है। जिसको निरस्त किया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी पत्रावली संख्या 1532 पर जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 20.9.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं विवादित पुस्तैनी मकान की मौका रिपोर्ट एवं शेष उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज तथा भाईयो की ओर से सहमति पत्र इत्यादि लिया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर